POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 फरवरी, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! सभी जानते हैं कि राष्ट्र की प्रगति और सर्वांगीण विकास सभी नागरिकों की शिक्षा एवं स्वास्थ और उसकी उपलब्धता पर निर्भर है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाती हैं और जीवन को बेहतर और सुचारू ढंग से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश के हर नागरिक को संवैधानिक एवं मानव अधिकारों के तहत शिक्षण संस्थाओं व अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त करने का हक है।

लेकिन आजादी के सात दशक बीतने के बाद भी हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि इन क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की सर्व उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को किस प्रकार हासिल किया जाए।

देखा जाए तो आज भी हमारे देश में सरकारी स्तर पर दोनों ही सेवाओं की पहुंच और उसकी गुणवत्ता के मामले में स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कि इस अवधि में सरकारों द्वारा इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए हैं, लेकिन देश की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या ये पर्याप्त रहे हैं?

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा करने पर सामने आता है कि आजादी के बाद एक लम्बी अवधि बीतने के बाद भी राजस्थान के सरकारी नियंत्रण वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में न तो शिक्षा का स्तर सुधर पा रहा है और न ही अभी तक विद्यार्थियों को कई बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं।

प्रदेश के हजारों स्कूलों में न तो उचित भवन है और न ही शिक्षक। स्कूलों में न पीने का पानी होता है न ही शौचालय। आज भी सरकारी स्कूल जनता की पसंद नहीं बन पाए। जबकि स्कूली शिक्षा की मजबूत नींव पर ही उच्च शिक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है।

दूसरी ओर प्रदेश में स्वास्थ्य से जुड़े मानव संसाधनों की स्थिति और जमीनी स्तर तक सुविधाओं की पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। गांवों में तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर न डॉक्टर मिलते हैं और न ही नर्स। नाममात्र की मुफ्त दवाएं भी लोगों को कभी-कभार ही मिल पाती है।

राज्य में बजट का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके अनुपात में शिक्षा और सेहत का बजट नहीं बढ़ रहा। पिछले दिनों नीति आयोग ने भी मौलिक अधिकारों के साथ ही देश में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की अहम जरूरत जताई है।

मेरा मानना है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसे जन साधारण के बीच सहभागिता और जनजागृति अभियान के रूप में संचालित किया जाए। हम इस दिशा में चीन से भी सबक ले सकते हैं, जिसने दोनों क्षेत्रों में असरदार और सख्ती से अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया है।

'ग्राम गदर' के इस अभियान में सभी ग्रामीण बन्धुओं और पाठकों की सहभागिता एवं विचार आमंत्रित हैं।

इलाज में लापरवाही: सोनी अस्पताल पर दस लाख रुपए हर्जाना

बजाज नगर निवासी कमलकांत शर्मा ने जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में जेएलएन मार्ग स्थित सोनी अस्पताल सहित डॉ.आराधना शर्मा, डॉ. दिनेश विजय व अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी की 15 साल की बेटी कृतिका की तबियत खराब होने पर 3 अक्टूबर 2006 को सोनी अस्पताल में भर्ती कराया। दो दिन बाद उसकी तबियत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में ले गए। उनकी अनुमति लिए बिना डॉक्टरों ने एनेस्थिसिया विशेषज्ञ की गैर मौजूदगी में उनकी बेटी के पेट में सेन्ट्रल लाइन डाली। जिससे अत्यधिक खून बहने से 6 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई।

मामले की सुनवाई पर मंच ने अस्पताल के दोनों चिकित्सकों को कृतिका के पेट में सेन्ट्रल लाइन डालकर उसके इलाज में गंभीर रूप से लापरवाही बरतने का दोषी माना। मंच ने माना कि मरीज की देखभाल में लगाई नर्स भी न तो योग्य डिग्रीधारी थी और न ही उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में था। वह नियुक्ति के योग्य नहीं थी। उपभोक्ता मंच ने सोनी अस्पताल सहित डॉ.आराधना शर्मा, डॉ. दिनेश विजय व अन्य पर दस लाख रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही परिवाद खर्च के तौर पर दस हजार रुपए के साथ हर्जाना राशि एक माह में कमलकांत शर्मा को अदा करने के निर्देश दिए हैं।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2018

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 37 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2018 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'किसानों की स्थिति'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2018 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2019 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

सरकारी अस्पताल में गारंटेड इलाज

प्रदेश में सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में किए वादे 'स्वास्थ्य का अधिकार' पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। इसका मसौदा 22 राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पार्टनर मिलकर तैयार करेंगे। इसे 'एश्योर डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज' का नाम दिया गया है। मसौदे का सबसे बड़ा बिन्दु गारंटेड गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

संभवतया सरकार यह गारंटी भी देगी कि हर ग्राम पंचायत पर एक सब-सेंटर होगा। तय आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल होगा। इसके लिए पैरामीटर तय होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

किसानों के लिए नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों को बिजली के जो एक लाख कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं वह जून तक दे दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पांच साल तक किसानों के लिए बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी।

जयपुर में राहुल गांधी की मौजूदगी में आयोजित किसान रैली में किसान आयोग का गठन करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग के जरिए प्रदेश के किसानों के सामने आने वाली सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। किसान अपने खेतों में फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां लगाएं। इसके लिए उन्हें 10 हैक्टेयर तक जमीन का भूमि उपयोग परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार ने बढ़ाई वृद्धावस्था पेंशन

राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है। प्रदेश में 75 वर्ष से कम आयु वाले बुजुर्गों को अब 500 रुपए की जगह 750 रुपए तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों को 750 रुपए की जगह 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इससें प्रदेश के करीब 45 लाख बुजुर्ग लाभान्वित होंगे।

पेंशन बढ़ोतरी के आदेश एक जनवरी से लागू होंगे। सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पेंशन में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

ग्रामीण योजनाओं की होगी मॉनिटरिंग

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं के धरातल पर हालात जानने के लिए अब जिला प्रभारियों की मॉनिटरिंग राज्य स्तर के अधिकारियों की टीम करेगी। इसके लिए मुख्यालय में तैनात 20 अफसरों को 33 जिलों का जिम्मा दिया गया है और जिलेवार समीक्षा के हिसाब से टीम गठित कर दी गई है।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने योजना की सफल क्रियान्विति, गुणात्मक परिसम्पत्ति अर्जन, आकर्षक आधारभूत ढांचा विकसित करने आदि की जिलेवार समीक्षा करने का निर्णय लिया है। यह अधिकारी जिलों में भ्रमण के दौरान दो पंचायत समितियों और प्रत्येक पंचायत समिति की दो पंचायतों की समग्र समीक्षा कर रिपोर्ट देंगे।

पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूल

सरकार ने प्रदेश के हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की कवायद शुरू कर दी है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को 12वीं तक की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

पंचायत स्तर पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खुलने का सबसे ज्यादा फायदा बेटियों को मिलेगा। पिछली सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए थे, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में स्कूल क्रमोन्नत नहीं हो पाए। अब नई सरकार इस घोषणा को पूरा करने में लगी है।

आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

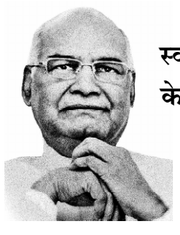

लोकसभा व राज्यसभा की स्वीकृति के बाद सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ मोदी सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे बिल ने कानूनी रूप ले लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जल्द ही आरक्षण के प्रावधानों से जुड़े नियम-कायदों को अंतिम रूप दे देगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह देश की युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा।

प्रदेश में हर छठा व्यक्ति बेरोजगार

राजस्थान में बेरोजगारी के हालात काफी चिंताजनक हैं। बेरोजगारी की स्थिति में राजस्थान चौथे पायदान पर पहुंच गया है। यहां तक कि बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति राजस्थान से बेहतर है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी की दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का हर छठा व्यक्ति बेरोजगार है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर पिछले तीन साल में सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंच गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन संकट ने बेरोजगारी बढ़ाई है। प्रदेश में इस समय बेरोजगारी दर 15 फीसदी है। देश के त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य ही बेरोजगारी में राजस्थान से ऊपर है। राज्य में बेरोजगारी की यह स्थिति राष्ट्रीय औसत से भी दोगुनी है।

महिलाओं को किया जाएगा जागरूक

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं व बालिकाओं के लिए शुरू की गई माहवारी स्वच्छता प्रबंधन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की कवायद की जा रही है।

योजना के तहत समुदाय में तथा स्कूलों में महिलाओं और किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूक किया जाएगा। पंचायत स्तर पर इससे जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी। स्कूलों में तथा समुदाय में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं व किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जांएगे। इस काम में स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, साथिन और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी सहयोग करेंगे।

जंगलों में लगाएंगे फलदार पौधे

वनमंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा है कि नर्सरी और आदिवासी क्षेत्र के वनों में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। ताकि आमजन को आय की प्राप्ति हो और जंगल भी हरा-भरा रहे। वहीं उन्होंने विदेशी बबूल को वनस्पति के लिए नुकसान दायक बताया और उनकी रोकथाम पर जोर दिया है।

उन्होंने यह बात झालाना स्थित राजस्थान वानिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान में रक्षा संस्था, डब्ल्यूटीआई, आइफा और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में कही। कार्यशाला में 23 राज्यों से आए विशेषज्ञों ने प्रस्तुतिकरण दिए। कार्यशाला में दूसरे दिन पक्षियों के बचाव और पुर्नवास पर भी मंथन किया गया।

बेटियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना को अगले सत्र से लागू करेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार का प्रथम चरण में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो सत्र 2020-21 से प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क मुहैया कराने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर